आकाशवाणी श्री विजयपुरम

दिनांक : 24.07.2026 समय : 1905

- प्रधान मंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक सत्र व्यर्थ नहीं जाने देंगे। परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
- भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी ने दिल्ली दौरे की प्रमुख चर्चाओं की जानकारी दी।
- सांसद विष्णु पद रे ने निजी विश्वविद्यालय विनियमन 2026 स्थगित कर द्वीप समूह में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की मांग की।
- अंडमान निकोबार की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से लोगों को परिचित कराने के लिए श्री विजयपुरम में आयोजित होगी कालापानी ट्रेल हेरिटेज वॉक।

<><><><><><><>

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि प्रश्न पत्र लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

<><><><><><><>

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी ने आज आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हाल ही में नई दिल्ली प्रवास के दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों तथा भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ द्वीप समूह के विकास और जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि इन बैठकों में द्वीपों से संबंधित कई विषयों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है और शीघ्र प्रगति की उम्मीद है। श्री तिवारी ने बताया कि केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओरांम के साथ हुई बैठक में ग्रेट निकोबार अवसंरचना परियोजना पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान मंत्री जी ने जनजातीय समुदायों के हितों

और उनकी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का भी भरोसा दिया। उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल के साथ हुई बातचीत में द्वीपों में पेयजल संकट के समाधान, बांध के निर्माण, वाटर मैनेजमेंट बोर्ड के गठन तथा जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन पर चर्चा की। इस अवसर पर मत्स्य पालन और पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी केंद्र सरकार के समक्ष विभिन्न सुझाव रखे गए। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंपे गए ज्ञापन में लद्दाख की तर्ज पर अंडमान एवं निकोबार में ग्रुप–बी और ग्रुप–सी के कुछ पदों पर स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने, डोमिसाइल नीति, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, मत्स्य पालन, पर्यटन, कनेक्टिविटी तथा रोजगार से जुड़े विषय शामिल किए गए।

<><><><><><><>

श्री तिवारी ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से मुख्यभूमि से दवाइयों की आपूर्ति में होने वाली देरी को कम करने के लिए जेम पोर्टल से संबंधित व्यवस्था की समीक्षा का सुझाव भी दिया गया है, ताकि आवश्यक दवाएं समय पर उपलब्ध हो सकें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने नीट परीक्षा का पुनः आयोजन कम समय में कराया तथा प्रश्नपत्र लीक जैसे मामलों में कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की व्यवस्था करने की दिशा में भी पहल की है। श्री तिवारी ने कहा कि अगले तीन वर्षों में सड़क, बिजली और पेयजल जैसी आधारभूत सुविधाओं में सुधार की दिशा में कार्य होंगे तथा 50 मेगावाट क्षमता के एलएनजी आधारित विद्युत संयंत्र के निर्माण से बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और केंद्र सरकार ने द्वीप समूह से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया है।

<><><><><><><>

सांसद विष्णु पद रे ने उप–राज्यपाल से प्रस्तावित अंडमान निकोबार द्वीप समूह निजी विश्वविद्यालय विनियमन–2026 को फिलहाल स्थगित करने और इसके स्थान पर द्वीप समूह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की दिशा में पहल करने का आग्रह किया है। 21 जुलाई को सौंपे गए ज्ञापन में उन्होंने कहा कि द्वीपवासी लंबे समय से केंद्रीय विश्वविद्यालय की माँग कर रहे हैं जबकि निजी विश्वविद्यालय की कोई स्पष्ट सार्वजनिक मांग सामने नहीं आई है। उन्होंने प्रस्तावित व्यवस्था में शिक्षाविदों, विश्वविद्यालय अनुदान

आयोग, शिक्षकों, छात्रों और जन प्रतिनिधियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देनेकी भी आवश्यकता बताई। सांसद ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना से किफायती उच्च शिक्षा, बेहतर शोध सुविधाएं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की नियुक्ति और द्वीपों की आवश्यकताओं के अनुरूप विशेष पाठ्यक्रम उपलब्ध हो सकेंगे। इस संबंध में ज्ञापन की प्रतियां प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष तथा अंडमान और निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव को भी भेजी गई हैं।

<><><><><><><>

सांसद विष्णु पद रे ने प्रशासन से सरकारी कॉलेजों के छात्रों को मिलने वाले मासिक छात्रवृत्ति को वर्तमान डेढ़ हजार रुपये से बढ़ाकर कम से कम चार हजार रुपये करने का आग्रह किया है। मुख्य सचिव को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई और जीवन–यापन की लागत के कारण मौजूदा छात्रवृत्ति छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने बताया कि यह मुद्दा उन्होंने अक्टूबर 2025 में भी उठाया था और शिक्षा सचिव ने दिसंबर 2025 में छात्रवृत्ति बढ़ाने के प्रस्ताव के प्रक्रिया अधीन होने की जानकारी दी थी। लेकिन नौ महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। सांसद ने कहा कि छात्रवृत्ति में अंतिम संशोधन वर्ष 2015 में किया गया था, जब इसे एक हजार रुपये से बढ़ाकर डेढ़ हजार रुपये किया गया था। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया है कि जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय, अंडमान कॉलेज, डॉ. बी.आर. अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान, महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय मायाबंदर, महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय कैंपबेल बे, डॉ. बी.आर. अंबेडकर राजकीय पॉलिटेक्निक, विधि महाविद्यालय तथा अन्य सरकारी शिक्षण संस्थानों के छात्रों के हित में छात्रवृत्ति बढ़ाने के प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय लिया जाए।

<><><><><><><>

अंडमान निकोबार प्रशासन का कला और संस्कृति विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास अंडमान नकोबार चैप्टर के सहयोग से श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में नियमित रूप से हेरिटेज वॉक आयोजित करेगा। इस पहल का उद्देश्य द्वीप समूह की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से पर्यटकों, स्थानीय लोगों, छात्रों और विरासत प्रेमियों को परिचित कराना है। इसके तहत

कालापानी ट्रेल हेरिटेज वॉक 30 जुलाई को सुबह साढ़े पाँच बजे से सुबह सात बजे तक आयोजित होगी। इस दौरान प्रतिभागियों को द्वीपों के इतिहास से जुड़ी महत्वपूर्ण विरासत स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। यह हेरिटेज वॉक पर्यटकों, छात्रों, फ्रीलांस और अधिकृत टूरिस्ट गाइड, टूर ऑपरेटरों के प्रतिनिधियों तथा विरासत में रुचि रखने वाले सभी लोगों के लिए खुली है। इच्छुक प्रतिभागी अधिक जानकारी और पंजीकरण के लिए कला और संस्कृति विभाग से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए 9434296432 पर फोन किया जा सकता है या artand.culture@and.nic.in पर ईमेल भेजा जा सकता है।

<><><><><><><>

दक्षिण अंडमान जिले के जिला मजिस्ट्रेट ने जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पी एम श्री केन्द्रीय विद्यालय–1 स्कूल से कार्मेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक जाने वाली सड़क पर सभी चार पहिया वाहनों की आवाजाही पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सड़क पर पुलिया निर्माण कार्य के चलते यह प्रतिबंध लगाया गया है और निर्माण कार्य पूरा होने तक लागू रहेगा।

<><><><><><><>